Date - 19 January 2022

‘देश के मेंटर’ कार्यक्रम

- हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार अपने प्रमुख ‘देश के मेंटर’ कार्यक्रम को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि बच्चों की सुरक्षा नहीं हो जाती। सभी संबंधित दोषों को ठीक नहीं किया जाता है।

बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCPCR):

- NCPCR का गठन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

Yojna IAS

- आयोग का जनादेश सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों पर भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप हैं।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है।
- यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012] के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में:

- नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को स्वैच्छिक सलाहकारों से जोड़ने के उद्देश्य से इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
- दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा बनाए गए ऐप के माध्यम से, 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग मेंटर बनने के लिए साइन अप कर सकते हैं, जो आपसी हितों के आधार पर छात्रों के साथ जुड़ेंगे।
- मेंटरशिप में कम से कम दो महीने की अवधि के लिए नियमित फोन कॉल्स शामिल हैं, जिसे बारी-बारी से अगले चार महीनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- विचार युवा सलाहकारों को उच्च शिक्षा और करियर विकल्पों जैसे मामलों में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें और दबाव से मुक्त हो सकें।
- अब तक 44,000 लोगों ने मेंटर के रूप में साइन अप किया है, 1.76 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं।

NPCR द्वारा उठाई गई चिंताएं:

- बच्चों को समान-लिंग वाले सलाहकारों से जोड़ना ही उन्हें दुर्व्यवहार से बचाने का एकमात्र तरीका नहीं है।
- संरक्षक के पुलिस सत्यापन का अभाव।
- साइकोमेट्रिक परीक्षण एक बच्चे के लिए संभावित खतरे के संदर्भ में किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रमाण मूल्यांकन नहीं है।
- बातचीत को फोन कॉल तक सीमित करना भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है क्योंकि "बच्चों से संबंधित अपराध फोन कॉल के माध्यम से भी शुरू किए जा सकते हैं।"
- बच्चों को ऐसी स्थितियों से बचाना विभाग की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में माता-पिता की सहमति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

Yojna IAS

‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार’

- हाल ही में, नागालैंड के ‘सोम’ जिला प्रशासन को ‘कोविड-**19** के प्रबंधन में आईसीटी का उपयोग’ श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार **– 2020-21**’ से सम्मानित किया गया है।
- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ‘सोम’ जिला प्रशासन ने ‘प्रशासन की सहायता में प्रौद्योगिकी’ नामक पहल के तहत कोविड-**19** महामारी के प्रबंधन और कठिनाइयों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर लागू किया है। आम जनता की। डीप लर्निंग जैसी विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया।
- इस व्यवस्था के तहत, विभिन्न योजनाओं और पहलों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कई निजी कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित ई-गवर्नेंस पर **24**वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया था।
- ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार’ प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।
- पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।

दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में राज्य की पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है।
- इस संबंध में जारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) इस साल अप्रैल महीने तक करीब **300** और नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा.
- हालांकि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी में कुल **2000** इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का है, जो राज्य में प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- इलेक्ट्रिक बसें कम से कम **120** किमी की दूरी तय करेंगी और राज्य में कुछ स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था की जाएगी।
- गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक ने सार्वजनिक परिवहन के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी।
- वर्तमान में कर्नाटक राज्य की सड़कों पर **25** इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इन बसों में रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएस), इमरजेंसी के लिए पैनिक बटन, ऑटोमेटिक बस व्हीकल लोकेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्टॉप रिक्वेस्ट बटन आदि फीचर शामिल हैं।

Yojna IAS

रविदासिया समुदाय

- हाल ही में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पंजाब में रविदासिया समुदाय के महत्व के कारण विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया है।
- राज्य सरकार और राजनीतिक दलों ने चिंता व्यक्त की कि 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती मनाने के कारण कई भक्तों को वाराणसी (एक स्मारक मंदिर में) में मतदान करने से रोक दिया जाएगा।
- हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार, गुरु रविदास की जयंती माघ महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।

परिचय:

- रविदासिया दलित समुदाय से हैं, जिनमें से अधिकांश लगभग 12 लाख की आबादी वाले दोआब क्षेत्र में रहते हैं।
- डेरा सचखंड बल्लन, जो दुनिया भर में उनके 20 लाख अनुयायियों के साथ सबसे बड़ा डेरा है, की स्थापना बाबा संत पीपल दास ने 20वीं सदी की शुरुआत में की थी।
- अतीत में सिख धर्म से निकटता से जुड़े होने के बावजूद, डेरा ने 2010 में दशकों पुराने संबंध तोड़ दिए और घोषणा की कि वे रविदासिया धर्म का पालन करेंगे।
- यह घोषणा वाराणसी में रविदास जयंती के अवसर पर की गई।
- वर्ष 2010 से, डेरा सचखंड बल्लन ने रविदासिया मंदिरों और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब को अपने स्वयं के ग्रंथ अमृतबनी से बदल दिया, जिसमें गुरु रविदास के 200 भजन थे।

गुरु रविदास:

Yojna IAS

- गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि संत थे और उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की।
- ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में एक मोची के परिवार में हुआ था।
- उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं की रचना के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की।
- उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया और ब्राह्मणवादी समाज की अवधारणा की खुले तौर पर निंदा की।
- उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर तत्काल प्रभाव डाला। उनकी लगभग 41 कविताओं को सिख धार्मिक ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' में भी शामिल किया गया था।

Swadeep Kumar

Yojna IAS